शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 जून 2013

सम्पादकीय

योग, उद्योग और सहयोग का अभाव है हमारी शिक्षा में

एक कहावत प्रसिद्ध है 'सौ पढ़ा और एक कढ़ा' अर्थात कोई अपने जीवनकाल में कितनी उपाधियां हासिल कर ले, सिद्धांतों को कितना ही रट ले, वह एक कौशल जानने वाले से हमेशा कमतर ही रहेगा। आज हमारे देश के सामने कौशल रहित युवाओं की फौज सबसे बड़ी चुनौती है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था में उत्पादक श्रम का कोई स्थान नहीं है। विद्यार्थियों द्वारा जितने प्रतिशत अंक अर्जित किए जा रहे हैं, उससे तो कभी-कभी यह लगता है कि या तो पाठ्यक्रम बहुत आसान है अथवा विद्यार्थियों के दिमाग बड़े हो गए हैं। लेकिन अधिक प्रतिशत पाने वाले ये विद्यार्थी आखिर अकुशल ही हैं। वे उस किसान से, उस कारीगर से, उस उद्यमी से बहुत कमतर हैं जो निरक्षर अथवा कम पढ़े-लिखे होकर भी राष्ट्रीय आमदनी में अपना कुछ-न-कुछ योगदान अवश्य दे रहे हैं। एक निश्चित अध्ययनकाल के बाद सरकारी और निजी क्षेत्रों में कौशल विकास के अनेक पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं, परंतु उसमें सभी विद्यार्थी शामिल नहीं होते। फलतः हमारे शिक्षण संस्थानों को बेरोजगारों का उत्पादन करने वाली फैक्ट्री का तमगा मिल गया है। हमारी शिक्षा में योग, उद्योग और सहयोग का कोई स्थान नहीं है। समाज में बढ़ रही संवेदनहीनता के लिए श्रमरहित शिक्षा ही जिम्मेदार है। शिक्षा से श्रम को बेदखल करने के परिणामस्वरूप समाज में श्रम के प्रति अरुचि और उपेक्षा का भाव बहुत गहराई तक पैठ गया है। गांव में एक ओर कहावत चलती है 'आधा पढ़ा हल से गया, पूरा पढ़ा घर से गया और ज्यादा पढ़ा देश से गया।' पढ़-लिख लेने का मतलब हो गया है अपने पारंपरिक मूल उद्योग को तत्काल तिलांजलि देना और नौकरी की दौड़ में शामिल हो जाना। कौशलरहित युवाओं की बढ़ती फौज को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर कौशल विकास अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस कौशल विकास को शिक्षण संस्थाओं से ही प्रारंभ किया जाना चाहिए।

अभी स्कूली शिक्षा में दसवीं और बारहवीं कक्षा को बोर्ड का दर्जा दिया गया है। इस ढांचे में संशोधन किया जाना चाहिए। पहले ग्यारहवीं कक्षा को बोर्ड का दर्जा मिला हुआ था। ग्यारहवीं कक्षा को पुनः कायम करते हुए विद्यालयीन स्तर पर विषय चयन से विद्यार्थियों को पूर्णतः मुक्त कर देना चाहिए। ग्यारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विद्यार्थी को सीधे कालेज में प्रवेश न देते हुए एक वर्ष के लिए कौशल विकास हेतु उसकी रुचि के क्षेत्र में भेजने का प्रबंध करना चाहिए। विद्यार्थी जिस क्षेत्र में कौशल विकसित करना चाहता है उसे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की होगी। एक वर्ष के कौशल विकास प्रशिक्षण के बाद युवा यह कहने की स्थिति में रहेगा कि उसके पास एक कौशल है। इससे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

ऐसी व्यवस्था करना होगी कि कौशल विकास प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के बिना किसी युवा को स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश नहीं मिले। अभी की स्थिति में विद्यार्थी के कम से कम पच्चीस साल केवल पढ़ने में ही जाते हैं। पूरी पढ़ाई के दौरान उसे ऐसा कोई कौशल नहीं सिखाया जाता, जिससे वह आत्मनिर्भर हो सके। महंगी होती उच्च शिक्षा के बोझ तले माता-पिता और पालक दबे जा रहे हैं। और उससे हासिल क्या हो रहा है कौशलरहित सैद्धांतिक ज्ञान! एक अध्ययन के अनुसार केवल ग्यारह प्रतिशत युवा ही उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं। अत्यधिक विपन्नता और गरीबी के चलते अनेक युवा आज भी अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ हैं। यदि विद्यार्थी के जीवन का एक वर्ष कौशल अर्जित करने में समर्पित किया जाए, तो देश का विकास तीव्र गति से सही दिशा में हो सकेगा। पण्डित और मल्लाह की वह कहानी तो प्रसिद्ध ही है जिसमें मल्लाह पढ़ा-लिखा नहीं था पर उसे तैरना आता था और पण्डित ज्ञानभार से लदा था, परंतु तैरना नहीं आता था। भारत में शिक्षा की ऐसी ही स्थिति है। जिनके पास कौशल है, उनके पास डिग्री नहीं है, जिनके पास डिग्री है वे कौशल शून्य हैं। पहले हम निरक्षर थे। सरकार ने हमें पढ़ने के लिए वजीफा दिया। पढ़कर हम साक्षर और जागरूक हो गए। पढ़ने के बाद हमें पता चला कि हमारा शोषण हो रहा है। हम इस शोषण को मिटाने के लिए नक्सली या आतंकवादी बन गए, क्योंकि हमारे पास असमानता की खाई को पाटने का और कोई कौशल नहीं था।

- डॉ पुष्पेंद्र दुबे